जनविश्वास की बहाली से ही मजबूत होगा देश..!

यह अविश्वास किसी एक सरकार, किसी एक वर्ष या दशक में पैदा नहीं हुआ है. जनता की जरूरतों पर सत्ता, सरकार, संस्थाओं, लोकतंत्र के चारों स्तंभों ने अनेकों बार कुठाराघात किया है. इससे सरकार, जवाबदेही वाली संस्थाओं और जनमानस के बीच परस्पर तालमेल बिगड़ा है. जनता को मूलभूत जरूरते जो उसका संवैधानिक अधिकार है, वह प्राप्त नहीं हो रही है.

किसी भी देश, समाज, संस्था अथवा परिवार की मजबूती का आधार आपसी विश्वास होता है. अगर बात देश की है तो फिर यह विश्वास सिर्फ किसी छोटे-बड़े समूह में नहीं आमजन के रूप में जनविश्वास के रूप में देखा जाना चाहिए. आज जनता में अजीब किस्म की झटपटाहट है. शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजमर्रा के कामों में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद से लेकर हर तरफ अफरा-तफरी मची है. एक प्रकार से जनता का विश्वास डिग रहा है. इस विश्वास की बहाली अवश्यंभावी है.

मतभेद भुलाकर, असहमति का सम्मान करते हुए देश मजबूत कैसे हो इस दिशा में सोचने और काम करने की जरूरत है. यह सामुहिक प्रयासों से संभव है. इसी से विश्वास की बहाली होगी. मतभेद को दूर करने के लिये काम होना चाहिए, मतभेद को दुश्मनी मानने से काम नहीं चलेगा. देश की 140 करोड़ की आबादी में से करीब 90 प्रतिशत से अधिक आबादी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, दैनिंदनी कार्यो को लेकर आने वाली परेशानी व सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा भाई भतीजावाद से परेशान है. इस कारण अविश्वास का यह संकट आबादी के इस बड़े अंतर में नजर आता है. यही संकट जनविश्वास को कमजोर कर रहा है.

सरकार, समाज और संस्थाओं के बीच निर्मित विश्वास से ही विकास की नींव मजबूत होती है. आज यह विश्वास डगमगा रहा है. इसको लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी चिंता जाहिर की है. आमजन को शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो यह उसका संवैधानिक अधिकार है. यह सुविधा देना सरकार का परम कर्तव्य है.

देश की 140 करोड़ की आबादी में से करीब 90 प्रतिशत से अधिक आबादी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, दैनिंदनी कार्यो को लेकर आने वाली परेशानी व सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा भाई भतीजावाद से परेशान है. इस कारण अविश्वास का यह संकट आबादी के इस बड़े अंतर में नजर आता है. यही संकट जनविश्वास को कमजोर कर रहा है.

यह अविश्वास किसी एक सरकार, किसी एक वर्ष या दशक में पैदा नहीं हुआ है. जनता की जरूरतों पर सत्ता, सरकार, संस्थाओं, लोकतंत्र के चारों स्तंभों ने अनेकों बार कुठाराघात किया है. इससे सरकार, जवाबदेही वाली संस्थाओं और जनमानस के बीच परस्पर तालमेल बिगड़ा है. जनता को मूलभूत जरूरते जो उसका संवैधानिक अधिकार है, वह प्राप्त नहीं हो रही है.

यहीं कारण है कि संघ प्रमुख को सार्वजनिक रूप से यह कहना पड़ा है कि आज शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा आम लोगो की पहुंच से दूर हो गई है. इन सुविधाओं ने व्यवसायिक रूप ले लिया है. मप्र, उप्र सहित कई राज्यों में सरकारी स्कूल बंद हो रहे है. पढ़ाई का स्तर गढ़बड़ाने, स्कूल भवनों की जर्जर स्थिति, शिक्षकों व सुविधाओं के अभाव में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या न्यूनतम हो गई है. जबकि निजी स्कूलों की शिक्षा मंहगी हो रही है. ऐसे में गरीबों के बच्चों की शिक्षा पर प्रश्नचिन्ह लग रहा है.

स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी स्थिति किसी से छुपी नहीं है. सरकार ने योजनाओं के माध्यम से नि:शुल्क उपचार की व्यवस्था की है लेकिन इसका पालन कितना हो रहा है यह मरीज और उसके परिजन बता सकते है. अस्पताल लूट के केन्द्र बन गए है. अस्पताल प्रबंधन मरीज और उसके परिजन की भावनाओं से हर पल खेलते नजर आते है.

कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, मीडिया का फोकस जनसुविधा रहता है लेकिन इसमें दिखावा अधिक होता है. आज की परिस्थितियों को लेकर जनता में लोकतंत्र के चारों स्तंभों के प्रति भरोसा डिगा है. अंतिम उम्मींदों का केन्द्र माने जाने वाली न्यायपालिका की भूमिका भी संदेहास्पद हुई है. जिस प्रकार से न्यायलय के निर्णय आ रहे है, जजों के आचरण सामने आ रहे है उससे इनके प्रति आस्था डिगने लगी है.

गोविंद बड़ोने
रीजनल हेड, नवभारत

चारों स्तंभों की कार्यप्रणाली से जनता के दिलों दिमाख में एक विचलन, बैचेनी, झटपटाहट जैसी स्थिति है. आजादी की स्थिति से, संस्थाओं से अविश्वास बड़ा है. इस विश्वास की बहाली से ही देश सशक्त, मजबूत और विदेशी ताकतों से लड़ने ही नहीं उनसे विजय प्राप्त करने में अव्वल होगा. विश्वास की बहाली को लेकर सभी को मिलकर प्रयास करने की जरूरत है. 140 करोड के देश में हमारे आपसी मतभेद हो सकते है. अलग-अलग भाषा, प्रांत, परिस्थिति के अनेकों कारणों से मतभेद संभव है. जब चार लोगो के परिवार में मतभेद हो सकते है तो इतने बड़े देश में मतभेद भी अवश्यंभावी है. क्यों नहीं हो सकते. मतभेद होने के बावजूद भी मतभिन्नता का उपयोग परिवार को मजबूत बनाने के लिये होता है. मतभेद भुलाकर, असहमति का सम्मान करते हुए देश मजबूत कैसे हो इस दिशा में सोचने और काम करने की जरूरत है. यह सामुहिक प्रयासों से संभव है. इसी से विश्वास की बहाली होगी. मतभेद को दूर करने के लिये काम होना चाहिए, मतभेद को दुश्मनी मानने से काम नहीं चलेगा.